उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यह बर्बरता है जिसके कारण सामूहिक हत्याएं हुई। यह सब कुछ वहाँ हुआ जिसको सुनकर सभी दुखी हैं।

इसका अन्य पहलू यह है कि तमिल लोग अभी भी उचित ढंग से बस नहीं पाए है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे एक दूत और एक अनुभवी व्यक्ति लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु मामले का निपटारा करने के लिये आज वहां गए हैं या जा रहे हैं। वे अभी ठीक तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं। वे गृहविहीन हैं और उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहा है। अतः अब हमें यह देखना है कि इतनी दूर से हम उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं उनको की जाने वाली सप्लाई अपर्याप्त है—औषधियां, घरेलू सामान और अन्य वस्तुएं—और इस समय आपकी श्रीलंका सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वे स्वयं ही घबरा रहे है। उन्हें अपनी सूझ-बूझ पर ही भरोसा नही है कि इस घटना के बारे में उनकी स्थिति क्या है। अन्य बात किसी महाशक्ति की ओर उनके सुझाव के बारे में उठाई गई है। जी हां, यह बिल्कुल स्पष्ट है वे किसी महाशक्ति का सहारा ले रहे हैं। इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किस हद तक सहायता ली जाएगी। परन्तु एक बात निश्चित है कि भौगोलिक-सामरिक महत्व की दृष्टि से इस महाद्वीप का बहुत अधिक महत्व है और जबकि एक महाशक्ति का हिन्दमहासागर में गतिविधियां इतनी बढ़ गई है कि वह अपना प्रभाव बढ़ा रही है तो विशेषकर यह जानते हुए 'ट्रिकोमाली' क्या है। मैं जानता हूं कि 'ट्रिकोमाली' दक्षिण एशियाई समुद्रों में सबसे अच्छा नौसेना का अड्डा है और यह बहुत ही आकर्षक है और सामरिक महत्व की दृष्टि से किसी के लिये भी यह आकर्षण का केन्द्र है। और जब इस प्रकार की गतिविधियों का पता चलता है कि कुछ महाशक्तियां किसी अन्य विचार से आगे बढ़ रहे हैं तो किसी का भी चिंतित होना स्वाभाविक है। हमने उस स्थिति को बड़े ध्यान से देखना है और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि सारे सदन का यह कहना है कि हम श्रीलंका के तमिलों के साथ हैं। सारा देश उनके साथ है। मैं उत्तर का रहने वाला हूं एरन्तु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के लोगों की भावताओं को मैंने व्यक्त किया है। वे दक्षिण के तमिलों के साथ हैं और प्रत्येक मुसीबत में उनका साथ देंगे। अतः से सदन के विचार हैं और सदन के विचार जानकर प्रसन्नता हुई है। अन्ततोगत्वा, स्थिति का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। मै यही कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार तथा उच्च कमान स्थिति पर नियंत्रण कर रही है वह संतुलित और प्रशंसनीय है और स्थिति पर नियंत्रण बलपूर्वक किया जा रहा है, यद्यपि ऐसा लगता नहीं है, परन्तु यह बलपूर्वक, भौगोलिक—सामरिक महत्व को देखते हुए तथा भौगोलिक—राजनैतिक दृष्टि से किया जा रहा है। और मैं उच्च कमान तथा अपनी सरकार को यही कह सकता हूं कि उन्होंने स्थिति पर बहुत सूझ-बूझ से नियंत्रण किया है यद्यपि इसमें कुछ ताकत का भी इस्तेमाल किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया गया।

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह मैंने सभा को राष्ट्रपति जयवर्धन के विशेष दूत के साथ अपनी बात-चीत के निष्कर्षों से सूचित किया था। उसके तत्काल बाद श्रीलका संसद के विपक्ष के नेता और टी० यू० एल० एफ०, श्रीलंका के

तमिलभाषी लोगों का प्रतिनिधित्व करते वाले प्रमुख दल के महासचिव श्री जी० अमृतलिंगम जाफना से दिल्ली के लिए चल पड़े । 14 अगस्त को भारत आने के बाद, उन्होंने हमारे विदेश मन्त्री और हमारे मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों तथा विभिन्न दलों के संसद सदस्यों से भेंट करने के अतिरिक्त मुझसे भी बातचीत की थी । कल मैंने एक बार फिर राष्ट्रपति जयवर्धन को टेलीफोन किया था ।

सभा को नवीनतम स्थिति से सूचित करना चाहती हूं । टी० यू० एल० एफ० की ओर से श्री अमृतलिंगम ने हमारी सेवाओं का भी स्वागत किया और कहा कि इससे उनके दल और श्रीलंका सरकार के बीच बातचीत के संबंध में मूलत: परिवर्तन आया हैं । अनेक वर्षों तक उन्होंने और उनके दल ने श्रीलंका द्वीपसमूह की संयुक्त ढाँचे के अंदर ही तमिल लोगों के उचित अधिकारों और आकांक्षाओं को पूरा करने की माँग की थी, परंतु वे कोई सहायतापूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असफल रहे । इसके विपरीत, तमिल भाषी लोगों को निरन्तर परेशान किया जाता रहा और उनके विरुद्ध नवीनतम अत्याचारों ने बात-चीत में उनके विश्वास को पूरी तरह समाप्त कर दिया । श्री अमृतलिंगम और उनके साथी पिछली पेशकशों के आधार पर बातचीत करने की सम्भावना की आशा नहीं करते हैं । बहरहाल, वह अनुभव करते हैं कि भारत के प्रयासों के फलस्वरूप, स्थिति बदल गई है और यह यद्यपि दोनों पक्षों के बीच मतभेद गहरे ही हैं, फिर भी हल की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं ।

समय की मांग है कि श्रीलंका के लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत की जाए । इसके बदले में उनके एक साथ रहने और स्थायी हल, जो तमिल भाषी लोगों अल्पसंख्यकों और सिंहली बहुसंख्यकों को संतुष्ट करें, निकालने का विश्वास पुन: कायम किया जा सकता है । उस स्थायी हल की खोज का कार्य भी यथाशीघ्र किए जाने की आवश्यकता है ।

ऐसा बातचीत के द्वारा ही किया जा सकता है । जैसाकि मैंने पहले कहा था, यह निर्णय करना श्रीलंका सरकार का काम है कि तमिल नेताओं के साथ बातचीत कैसे और कब की जाए । परन्तु हमारी गहन चिन्ता के कारण हमने हर उस सहायता की पेशकश की थी, जो हम दे सकते हैं । किसी समझौते पर पहुंचने के लिये दोनों पक्षों को एक दूसरे से बात करनी आवश्यक है । बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और हमारे प्रयास का उपयोग करने के लिए मैंने राष्ट्रपति जयवर्धन और अन्य से मिलने के लिए एक विशेष दूत भेजने की पेशकश की थी । कल शाम मेरे लिए टेलीफोन पर बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जयवर्धन मेरे सुझाव से सहमत हो गये थे । तदनुसार, मैंने अपने प्रतिष्ठित और अनुभवी राजनयिक श्री जी० पार्थ सारथी को इस नाजुक और महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लेने को कहा था । वे अगले सप्ताह कोलम्बो जाएंगे ।

मैंने राष्ट्रपति जयवर्धन से सुरक्षा की और बिशेषकर विस्थापित कैम्पों में सुरक्षा की नवीनतम स्थिति के संबंध में सामान्य रूप से पूछा था । उन्होंने मुझे बताया कि स्थिति लगातार सामान्य होती जा रही है और अब केवल कुछ हजार लोग ही कैम्पों में हैं । राहत सप्लाई के संबंध में मेरे प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने कहा कि उनके पास काफी खाद्यान्न और कपड़े है परन्तु

वह हमारे उच्चायुक्त के निरन्तर सम्पर्क बनाए रखेगे, शायद किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाए।

राष्ट्रपति जयवर्धन और मैं निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने को सहमत हो गए हैं। वह इस बात पर भी सहमत थे कि उनके भाई जिनके साथ हमारी उपयोगी बातचीत हुई थी, उनके विशेष दूत के रूप में कार्य करते रहेंगे।

इस सभा में बार-बार हुई चर्चा के दौरान, माननीय सदस्यों ने घटनाओं पर अपनी भावनाओं की तीव्रता अभिव्यक्त की थी। हमारे देश के सभी वर्गों के लोग यही भावना रखते हैं, जो दल और अन्य मतभेदों से परे है। मैं इन दुखद घटनाओं पर तमिलनाडु में अपने भाइयों और बहनों की भावनाओं को भी विशेष रूप से जानती हूं। जैसा कि मैंने राज्यसभा में कहा था, भारत में अथवा कहीं भी तमिल लोगों की व्यथा हमारे पूरे देश की व्यथा है। श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों द्वारा भुगती गई पाश्विकता और निष्ठुर हिंसा का श्री अमृतलिंगम द्वारा यहां पर स्पष्ट वर्णन किया गया था। मेरी सरकार और स्वयं मैं श्रीलंका सरकार को अपना रोष और चिन्ता व्यक्त करते रहे हैं।

फिर भी हम जो कहते हैं या करते हैं उसके प्रभाव का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने स्थिति की नाजुकता और कठिनाई को समझा जो, जिससे हमें निपटना है। मैं उनकी इस समझदारी और सरकारी पक्ष को उनके समर्थन के लिए आभारी हूं।

ऐसी परिस्थितियों में संयम रखते हुए अडिग रहने की आवश्यकता होती हैं। अपनी नीति निर्धारित करने के लिए ये चीजें अवश्य जारी रहनी चाहिए। इन सबसे बढ़कर, हम एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश में हैं, जो साम्प्रदायिक तनाव से मुक्त हो तथा श्रीलंका के कोई स्थायी राजनैतिक समाधान खोजने हेतु सभी सम्प्रदायों के नेताओं के प्रयासों में सहायक हो। हम आशा करते हैं कि दोनों पक्ष इस संबंध में ठोस उपाय करेंगे। राष्ट्रपति जयवर्धन तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को इसी के लिए मनाने का काम मैंने अपने दूत को सौंपा है।

**श्री रशीद मसूद** (सहारनपुर) : मोहतरम स्पीकर साहब, श्री लंका के मामले पर हम लोग अपने-अपने ख्यालात जाहिर कर रहे हैं। बार-बार इस हाउस मे बहस का मतलब यह है कि हमारे और उनके ताल्लुकात बहुत करीबी हैं। हमारे उनसे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। कभी हम एक ही मुल्क का हिस्सा हुआ करते थे। हिन्दुस्तान में कोई बात होगी तो उसका असर पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पड़ोसी देशों मे अगर कोई बात होती है तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है।

1919 में जब महात्मा गांधी अमृतसर सेसन में शामिल हूए, उसके फौरन बाद एक तमिल सख्स ने सीलोन में आजादी लड़ाई के लिये "सीलोन कांग्रेस" की बुनियाद डाली। उस लड़ाई में जो सीलोन की आजादी के लिए हुई जहां सिंहलीज ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया वहां हमारे तमिल भाई एक कदम भी पीछे नहीं रहे। लेकिन सीलोन के आजाद होने के बाद वोट

की सियासत ने उस मुल्क के तमाम लोगों को मुसहिद नही रहने दिया। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था बदकिस्मती से इस मामले में हिन्दुस्तान की तारीख और सीलोन की तारीख कुछ मुख्तलिफ है। कुछ लोगों के हकों को वे छीनते रहे—

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : (बम्बई उत्तर पूर्व) आपका सुझाव क्या है ?

**श्री रशीद मसूद** : आपको बताऊंगा। हमला नहीं कराऊंगा।

**श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : वहां जाना चाहिये। हमारे प्रभाव में आ जाए तो अच्छा होगा।

**श्री रशीद मसूद** : शुक्रिया।

आजादी के फौरन बाद सिटिजनशिप एक्ट ने वहां के एक लाख तमिल लोगों को शहरियत के हकूक से महरूम कर दिया और वहां से इन शकों शुबहाय की बुनियाद पड़ गई कि वहां की मेओरिटी कहाँ की माइनोरिटीज को वे हकूक नहीं देना चाहती जो माइनोरिटीज को मुख्तलिफ मुल्कों में मिले हुए है। आजादी के लिहाज से मैं समझता हूं कि 68 परसेंट के करीब बौद्ध लोग हैं वहां, सत्तरह साढ़े सत्तरह परसेंट हिन्दू हैं, सात परसेंट के करीब ईसाई है और सात परसेंट के करीब मुसलमान और बाकी लोग हैं। इस लिहाज से करीब-करीब इतने ही नस्ल के लिहाज से तमिल की तादाद है, 17-18 परसेंट के करीब है। जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने बताया 1948 से लेकर 1983 तक मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ किस्म के मुजालिम उन पर होते रहे और उनके मसलों को हल करने की कोशिशें भी होती रहीं। इन प्राबलैम्ज को हल करने में हिन्दुस्तान ने भी अपना हिस्सा अदा किया। जैसे बताया गया है कि बंदरनाव के और शास्त्री जी के बीच पैक्ट हुआ जिसमें साढ़े पांच लाख के करीब आबादी को हमने लेने की बात कही थी और साढ़े तीन लाख के करीब लोगों को उन्होंने शहरियत के हकूक देने की बात कही थी। अगर उस पर अमल हो जाता तो। अगर उस पर अमल हो जाता तो शायद आज यह जो सिलसिला मुजालिम का शूरू न हुआ होता उसके बाद जब जबान का सवाल आया उस मामले से भी बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल किया गया। तब अगर सिंहलीज के साथ-साथ तमिल को भी वही मुकाम—दे दिया जाता तो शायद यह दूरी जो बढ़ रही थी उसको घटाने में मदद मिल सकती थी। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि इत्तिफाक से हमारे हालात में और सीलोन के हालात में बहुत मुताल्कित है। उन हालात को हमें भी पेशेनजर रखना चाहिये और उसी लिहाज से सोचना चाहिये।

दो तीन बातें हैं जिनकी वजह से बहुत बड़ा जहन पर बोझा पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखबारात में जो मुख्तलिफ जरायों से खबरें आती हैं वे ज्यादा सही हैं बनिस्वत उनके जो मुहतरिमा प्राइम मिनिस्टर साहिबा और वहां के सदर बराहम करते है। हमारी इत्तिला यह है—और मैं समझता हूं कि सही भी है कि मिलिटरी और दूसरे लोगों द्वारा जो मुजालिम हुए हैं तमिलज पर उनकी मदद के बारे में आपकी पिछले दिनों सीलोन सरकार से बातचीत हुई थी।